मेहनतकशों का पैग़ाम मेहनतकशों के नाम

मज़दूर मोर्चा

पाक्षिक

वर्ष 27 अंक 5 फरीदाबाद, वीरवार, 16-31 जनवरी 2014 फोन : - 9999595632 ₹ 2

श्रम विभाग में यूनियन रजिस्ट्रेशन का काला कारोबार
कमिश्नर साहब, ये कैसी सुरक्षा? 3

देश की इज्जत को बट्टा लगाती
एक राजनीतिक–देवयानी खोब्रागड़े 4

अमीरों के लिए धन दौलत और ग़रीबों के लिए भजन
ठग विद्या पढ़ाने वालों को नोबेल पुरस्कार 6

मंजूर है 'आप' की रैली : नामंजूर
'कद्दावर नेता' वाली शैली 8

राजा के दरबार में खड़ी जनता आम आदमी का कुछ नहीं बनता

वास्तविक लोकतंत्र, जिसकी बात आम आदमी पार्टी करती है, में आम आदमी को केजरीवाल दरबार के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं होनी चाहिये। और विकेन्द्रीकरण का मतलब यह नहीं कि सरकार कॉल सेंटर में बदल जाय।

नीयत की तरह नीति भी ठीक हो

दिल्ली मज़दूर मोर्चा ब्यूरो

लोकतन्त्र को समर्पित 'आप' पार्टी की दिल्ली सरकार का असली इम्तिहान इस बात में है कि वह अपना प्रशासन आम आदमी के मतलब से चलाये। हालांकि अभी तक उनकी घोषणाओं में ऐसा ही है, पर व्यवहार में उनकी सरकार वही सब प्रक्रियायें अपना रही है जो किसी अन्य पार्टी की नई-नई बनी सरकार अपनाती है। मन्त्रियों द्वारा छापेमारी, पार्टी कार्यकर्ताओं द्वारा आक्रामक रूप से प्रशासनिक मशीनरी की खोज खबर एवं मुख्यमंत्री का जनता दरबार ऐसे ही कदम हैं जो केजरीवाल सरकार द्वारा उठाये जा रहे हैं।

केजरीवाल ने मुख्यमंत्री बनते ही शुरूआती घोषणाओं में ही हर शनिवार को दिल्ली सचिवालय में जनता दरबार लगाने की घोषणा की। इसमें नया कुछ नहीं है। कांग्रेसी और भाजपाई मुख्यमंत्री भी यही करते हैं। चौटाले, मुलायम, मायावती, जयललिता भी यही करते हैं। सभी के राज में जनता को राजाओं के दरबार में धक्के खाने पड़ते हैं। जाहिर है, लोकतन्त्र में ऐसा नहीं होना चाहिये।

पहले ही शनिवार के दरबार में दिल्ली के आम आदमी की ऐसी तैसी हो गई। पचासों हज़ार आदमी इकट्ठा हो गये और सरकार को पूरा आयोजन रद्द करना पड़ा। सरकार की जग-हंसाई हुई सो अलग। केजरीवाल ने माफ़ी मांगते हुए यह कहकर पल्ला झाड़ लिया कि वे लोगों की आशाओं की व्यापकता का अनुमान नहीं लगा पाये। आगे से, उनके अनुसार, जनता दरबार के लिये बेहतर व्यवस्था की जायेगी।

बेहतर व्यवस्था से केजरीवाल का मतलब है कि तमाम आने वालों के शिकायतपत्रों को स्वीकारने में धक्का-मुक्की नहीं होगी, उनके बैठने इत्यादि की समुचित व्यवस्था होगी और सरकारी कार्यवाही का लेखा जोखा ठीक होगा। यह उनका सोचना है। पर हकीकत यह है कि पहली बार 50 हज़ार शिकायतकर्ताओं को यदि ठीक से अपनी शिकायत दर्ज कराने का मौका मिल गया तो अगली बार 70 हज़ार और उसके बाद संख्या लाख भी पार कर जायेगी।

शेष पेज 2 पर

मात्र अमेठी, अहमदाबाद क्यों नहीं ?

प्रधानमंत्री पद के दो घोषित उम्मीदवार हैं। इनमें से राहुल गांधी के चुनाव क्षेत्र अमेठी पर 'आप' पार्टी' के सिपहसालार कुमार विश्वास ने धावा बोल दिया है। दूसरे उम्मीदवार नरेन्द्र मोदी के अहमदाबाद को अभी छुआ भी नहीं गया है। ऐसा क्यों? अमेठी में कुमार विश्वास ही क्यों?

दोनों प्रश्न आपस में जुड़े हुए हैं। आज 'आप' का जुझारू मुखौटा बने कुमार विश्वास अन्ना आन्दोलन तक महज सफ़ल मंचीय कवि के रूप में जाने जाते थे। आन्दोलन के दौर में भी वे मंचों पर कविता पाठ करते रहे जिससे उन्हें भारी भरकम रकम भी मिलती थी। इसी क्रम में अहमदाबाद के ऐसे ही एक जमावड़े में नरेन्द्र मोदी मुख्य अतिथि बने और विश्वास ने उन्हें भगवान शिव का अवतार बता कर कसीदे पढ़े। शिव ही क्यों? इसलिये, क्योंकि शिव भी संहार के देवता हैं और मोदी गुजरात में मुसलमानों के संहार के लिये जाने जाते हैं। इसी धुन में विश्वास ने मोदी के 'ब्रह्मचर्य' को भी नमन करते हुए स्त्रियों को अपमानित करनेवाली मंचीय चुटकलेबाज़ी भी जम कर लोगों को परोसी।

लिहाजा किस मुंह से कुमार विश्वास अहमदाबाद जायें? और किस हौसले से 'आप' उन्हें मोदी के खिलाफ़ उतारे? न मोदी ने गुजरात नरसंहार के लिये माफ़ी मांगी है और न कुमार विश्वास ने संहारक मोदी के सम्मान में पढ़े कसीदों के लिये।

वैसे तो विश्वास को अमेठी ही भेजना 'आप' की भी राजनैतिक आवश्यकता बन गयी है। अमेठी में लगातार राहुल गांधी को गालियां निकाल कर कांग्रेस को उकसाया जा सकता है कि वह दिल्ली में 'आप' सरकार से समर्थन वापस ले ले। जाहिर होता जा रहा है कि 'आप' का नेतृत्व अभी दिल्ली में सरकार चला पाने की स्थिति में नहीं हो सका है। लिहाजा उन्हें चिन्ता है कि यदि उनकी सरकार ऐसे ही चलती रही तो लोक सभा चुनाव आने तक उनकी क्षमता को लेकर कई सवाल खड़े हो जायेंगे।

ऐय्याशियां : एक करोड़ से सौ करोड़ तक!

उत्तर प्रदेश की 'समाजवादी' सरकार के 9 मन्त्रियों की एक करोड़ की लागत वाली विदेश यात्रा पर सही ही चौतरफ़ा हमले हो रहे हैं। जनता के पैसे से ऐसी ऐय्याशी की यात्रायें न पहली हैं न आखरी। हर राज्य के मन्त्री/विधायक/अफ़सरशाह ऐसे दौरे जब-तब करते ही रहते हैं। गुजरात के मुख्यमंत्री नरेन्द्र मोदी जो भाजपा के प्रधानमंत्री पद के घोषित दावेदार हैं, का तो असली दर्द ही यह रहा है कि अमेरिका की ऐय्याश यात्राओं के लिये उन्हें वीज़ा नहीं मिल पा रहा। यदि कभी इन तमाम यात्राओं का लेखा-जोखा किया जाय तो एक ही निष्कर्ष निकलेगा- जनता के हज़ारों करोड़ राजकीय ऐय्यशियों में डुबो दिये गये।

यह रास्ता भी दूसरों को कांग्रेस ने ही दिखाया है। महात्मा गांधी की सादगी का पाठ तो स्वतंत्रता उपरांत सत्ता में आने के कुछ वर्षों बाद ही कांग्रेसी शीर्ष नेताओं ने भुलाना शुरू कर दिया था। स्वयं प्रधानमंत्री जवाहर लाल नेहरू इसके अगुआ रहे। श्रीमती इन्दिरा गांधी ने तो सरकारी भ्रष्टाचार के बेलगाम होने को यह कह कर उचित ठहराया कि ''भ्रष्टाचार वैश्विक परिघटना है।'' उनके कार्यकाल में प्रधानमंत्री ही नहीं मुख्यमन्त्रियों/मन्त्रियों की जीवनशैली पंचतारा होती चली गयी। श्रीमती गांधी के पड़ावों के लिये तो विश्रामगृहों पर ही करोड़ों खर्च कर उनकी तबियत के मुताबिक सजाया संवारा जाता था। राजीव गांधी के प्रधानमंत्री बनने पर तो खुले रूप में पंचसितारा संस्कृति नंगी होकर सामने आ गयी।

विदेशी दौरों में नियमित उड़ानों की बज़ाय प्रधानमंत्री के लिये नियमित रूप से एयर इन्डिया की चार्टर्ड उड़ान का प्रावधान होने लगा। इसके लिये सबसे बड़े जम्बो जेट बोईंग 747 को 2 सप्ताह पहले मुंबई में ग्राउंड कर उसकी साज़-सज्जा शुरू हो जाती। जहाज में प्रधानमंत्री के लिये बेडरूम, लाउंज और कांफ्रेस रूम तैयार किया जाता। बाकी अमले की हैसियत के अनुसार सुविधायें बनाई जातीं। इनमें मीडिया कक्ष एवं शराबखाना प्रमुख होते। सारे अमले को कीमती तोहफ़े दिये जाते। सभी का खना-पीना-शराब मुफ़्त। हर विदेशी जमीन पर सारा अमला (100 के लगभग) पंचसितारा होटलों में ठहरते। स्वयं प्रधानमंत्री हमेशा शहर के सबसे महंगे होटल के सबसे मंहगे कक्ष (स्वीट) में रुकता। चार देशों की ऐसे सम्मिलित यात्रा पर कुल खर्च 100 करोड़ का आता। राजीव गांधी के बाद आये हर प्रधानमंत्री, कांग्रेसी नरसिंह राव से लेकर भाजपाई अटल बिहारी तक और अब मनमोहन भी इसी परम्परा को निभाते आ रहे हैं। आज़म खान के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश के मन्त्रियों की ऐय्याशी की नुक्ताचीनी करने वालों को भी जब मौका मिलेगा, वे भी यही करेंगे।

-अमर

ख़बर दार

भ्रष्टाचार पर उपदेश और 'आदर्श' की दीक्षा

वाड्रा हैं राहुल की असली अग्निपरीक्षा

मज़दूर मोर्चा ब्यूरो

दिसम्बर 2013 में 4 विधान सभाओं के चुनावों में मुंह की खाने के बाद राहुल गांधी ने लोकपाल से लेकर तमाम ऐसे कानूनों के चैम्पियन की भूमिका निभानी शुरू कर दी है जो उन्हें भ्रष्टाचार विरोध की लहर में अग्रणी योद्धा दिखा सकें। उनकी पहल पर दावा किया जा रहा है, लोकपाल विधेयक संसद द्वारा पारित किया गया। उनके फ़टकारने के बाद महाराष्ट्र सरकार ने आदर्श सोसायटी घोटाले की रपट को कार्यवाही हेतु आंशिक रूप से स्वीकार किया। इसके पहले राहुल की सार्वजनिक नाराजगी के चलते मनमोहन सरकार को वह अध्यादेश वापस लेना पड़ा था जो भाजपा के समर्थन से दाग़ी नेताओं को चुनाव लड़ने के अयोग्य ठहराने वाले सर्वोच्च न्यायालय के फ़ैसले से राहत देता था।

कई वर्षों से एक से बढ कर एक मनमोहन सरकार के घोटाले निकलकर सामने आ रहे थे और राहुल की खामोशी टूट नहीं रही थी। अब, अचानक उन पर भ्रष्टाचार विरोधी मुहिम के नायक बनने का ऐसा भूत सवार हुआ दिखता है कि वे आगामी संसद सत्र में कोईआधा दर्जन लम्बित भ्रष्टाचार विरोधी विधेयकों को पारित कराने की तैयारी में जुटे हैं। फ़रवरी के शुरू में होने वाला यह अधिवेशन बेशक छोटी अवधि का राहेगा पर इन बिलों का पारित होना राहुल की साख के लिये अनिवार्य माना जा रहा है।

(खल) नायक

आदर्श सोसायटी घोटाले पर महाराष्ट्र सरकार की लीपापोती को लेकर राहुल गांधी ने नाराजगी जताने के लिये कांग्रेसी मुख्यमन्त्रियों की दिल्ली में बुलाई बैठक को चुना। जब वे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान को इस विषय में निर्देश दे रहे थे

शेष पेज 2 पर